सुभाष चंद्र

बनाम

राज्य (चंडीगढ़ प्रशासन) और अन्य

15 नवंबर, 1979

[वी.आर. कृष्णा अय्यर और आर.एस. पाठक, जे.जे.]

दंड प्रक्रिया संहिता, धारा 321, 494 - याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि उसके घर में चोरी हुई थी और कई कीमती सामान खो हो गए थे। पुलिस ने संपत्ति को बरामद किया। आखिरकार, विचारण न्यायालय द्वारा दो अन्य व्यक्तियों के खिलाफ भी आरोप तय किए, उन्होंने सहयोग किया था। आपराधिक मामले के विचाराधीनता रहने के दौरान, सहायक लोक अभियोजक ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 321 के तहत अभियोजन द्वारा प्रह्याहरण करने के लिए इस आधार पर कि एक वरिष्ठ अधिकारी द्वारा नए सिरे से अनुसन्धान पर कथित तलाशी और जब्ती संबंधित पुलिस अधिकारी द्वारा एक साजिश के रूप में पाई गई थी ताकि आरोपी पर एक निश्चित दीवानी मुकदमे को वापस लेने के लिए दबाव डाला जा सके, आवेदन किया गया। न्यायालय को एक पूर्ण आवेदन की आवश्यकता थी, सहायक लोक अभियोजक ने प्रत्याहरण के लिए एक नई और अधिक विस्तृत याचिका दायर की, जिसे अंततः विचारण न्यायालय द्वारा स्वीकार कर लिया गया, याचिकाकर्ता के इस विरोध के बावजूद कि प्रत्याहरण जौहरी द्वारा राजनीतिक प्रभाव से प्रेरित था, जिसके कारण उच्च पक्षों ने सहायक लोक अभियोजक को उस आरोपी से संबंधित मामले से पीछे हटने का निर्देश दिया। यह आरोप लगाया गया था कि सहायक लोक अभियोजक ने उक्त निर्देशों का पालन करने में स्वतंत्र दिमाग का उपयोग नहीं किया। फिर भी विचारण न्यायालय ने सहायक लोक अभियोजक के अनुरोध को स्वीकार कर लिया और शेष दो अभियुक्तों के खिलाफ मामला जारी रखते

हुए जौहरी को दोषमुक्ति का निर्देश दिया। याचिकाकर्ता द्वारा उच्च न्यायालय के समक्ष पुनरीक्षण में आदेश पर असफल विरोध किया गया था।

संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत अपील करने के लिए विशेष अनुमति द्वारा, याचिकाकर्ता की ओर से यह तर्क दिया गया था कि (i) न्यायालय में पेश होने वाला मामला न्यायाधीश को इसके बारे में जाने बिना दूसरी पुलिस जांच के अधीन नहीं हो सकता है, (ii) कार्यपालिका के राजनीतिक विचार लंबित कार्यवाही को वापस लेने के प्रस्ताव को दूषित करते हैं, और (iii) लोक अभियोजक को भेजे गए और उसके द्वारा किए गए मामले से हटने का जिला मजिस्ट्रेट का आदेश, धारा 494 का अनुपालन है।

याचिका को ख़ारिज करते हुए अभिनिर्धारित किया:

जब कोई अपराध किया जाता है, तो अपराध का आकलन और सजा देना या, वैकल्पिक रूप से, आरोपी को उन्मोचित करना या दोषमुक्त करना देश की न्यायालयों द्वारा प्रशासित आपराधिक न्याय प्रक्रिया का हिस्सा है। आपराधिक न्याय देना कार्यपालिका का कार्य नहीं है और हमारी व्यवस्था में न्यायाधीशों को बदला नहीं जा सकता। [47-ए]

जब कोई मामला आपराधिक न्यायालय में लंबित होता है, तो इसकी प्रक्रिया और प्रगति दंड प्रक्रिया संहिता या अन्य प्रासंगिक क़ानून द्वारा नियंत्रित होती है। न्यायालय में किसी जांच या मुकदमे को रोकना और वापस बुलाना, अधिनियम में दिए गए तरीके और सीमा को छोड़कर, अपने आप में अधिनियम का उल्लंघन है। जो कुछ भी करने की आवश्यकता है वह कानून के अनुसार किया जाना चाहिए। हमारे संवैधानिक आदेश के तहत न्याय प्रशासन का कार्य, उन लोगों का है जिन्हें न्यायिक शक्ति सौंपी गई है। न्यायालयी प्रक्रिया के निर्बाध प्रवाह के कुछ अपवादों में से एक सीआरपीसी की धारा 321 है। लेकिन यहाँ भी यह लोक अभियोजक है न कि कोई

कार्यकारी प्राधिकारी, जिसे संहिता द्वारा अभियोजन से हटने की शक्ति सौंपी गई है, और वह भी न्यायालय की सहमति से। संहिता में दिए गए तरीके और सीमा को छोड़कर, किसी न्यायालय में किसी जांच या मुकदमे में हस्तक्षेप करना, रोकना या उसे रद्द करना अराजकता है। आपराधिक न्याय के समान मार्ग को कार्यपालिका द्वारा विफल नहीं किया जा सकता है, चाहे आरोपी कितना भी उच्च क्यों न हो, हालांकि सरकार को यकीन है कि कोई मामला झूठा है, हालांकि, उन शक्तियों के लिए अभियोजन जारी रखना अप्रिय है जो अहंकार, स्नेह या अन्य महान या अपमानजनक विचार के कारण न्यायालय के न्याय को बाधित करना चाहते हैं। न्यायालयी प्रक्रिया के इस निर्बाध प्रवाह के बहुत कम अपवादों में खंड 494 सी.आर.पी.सी. शामिल है। यहाँ भी, लोक अभियोजक को संहिता द्वारा न्यायालय की सहमति से अभियोजन से हटने की सीमित शक्ति सौंपी गई है, जिसके बाद मामला समाप्त हो जाता है। कानून ने जिसे प्रज्वलित किया है, उसे केवल कानून ही बुझा सकता है। [47 डी-एच, 48 ए]

कानून और व्यवस्था को बढ़ावा देना लोक न्याय का एक पहलू है। सार्वजनिक नीति के आधार पर अभियोजन प्रत्याहरित करने की आवश्यकता हो सकती है। झूठा और परेशान करने वाले अभियोजन पक्ष को आगे बढ़ने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। लेकिन शक्ति का सावधानीपूर्वक प्रयोग किया जाना चाहिए, और संतुष्ट होने वाली वैधानिक एजेंसी पहली बार में लोक अभियोजक है, न कि जिला मजिस्ट्रेट या अन्य कार्यकारी प्राधिकारी। अंततः, न्यायायलय की सहमति अनिवार्य है। [48 जी-एच]

राजनीतिक प्रभाव के आरोप के समर्थन में कोई साक्ष्य नहीं था। उसी समय, जिला मजिस्ट्रेट ने सहायक लोक अभियोजक को प्रयाहरित लेने का निर्देश देते हुए अवैध रूप से काम किया। यह आरोप लगाया गया है कि कार्यकारी पक्ष की ओर से मामले का दूसरा अन्वेषण, जिसके कारण यह पता चला कि पहले की जांच प्रेरित थी, पहले सूचना देने वाले से पूछताछ करने में चूक से दूषित हो गई थी। यह सहायक लोक

अभियोजक के लिए एक ऐसा मामला था जिस पर यह तय करते समय विचार करना था कि अभियोजन से पीछे हटना है या नहीं। यह बहुत स्पष्ट है कि सहायक लोक अभियोजक ने अपने समक्ष मौजूद सामग्री पर एक स्वतंत्र निर्णय लिया और जिला मजिस्ट्रेट के निर्देशों के अंधे अनुपालन में कार्य नहीं किया। [50 एफ-एच, 51 ए]

कानून का शासन कार्यकारी अधिकारियों को मामलों को वापस लेने के मामले में न्यायसंगत प्रक्रिया से सावधान करता है। चूंकि न्यायालय इस बात से संतुष्ट थीं कि लोक अभियोजक ने जिला मजिस्ट्रेट के निर्देश को नहीं माना, लेकिन न्यायालय के समक्ष रखी गई सामग्री के बारे में खुद को सूचित करने का एक स्वतंत्र अध्ययन किया और फिर अभियोजन से पीछे हटने की अनुमति मांगी, इसलिए इस न्यायालय ने विचारण न्यायालय के आदेश को उलटने से इनकार कर दिया। [51 एफ-एच]

एम. एन. शंकरनारायण नायर बनाम पी.वी. बाल कृष्ण और अन्य, एआईआर 1972 एससी 496: बंसी लाल बनाम चंदन लाल, एआईआर 1976 एससी. 370: बलवंत सिंह और अन्य बनाम बिहार, एआईआर 1977 एससी. 2265, पुष्टि की।

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार: विशेष अनुमति याचिका (अपराधिक) संख्या 2076/1978

पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा आपराधिक पुनरीक्षण संख्या 181/77 में पारित निर्णय और आदेश दिनांक 17-3-1978 से उत्पन्न।

आर.एल.कोहली, एस.के.सभरवाल और सुभाष चंद्र, याचिकाकर्ता की और से।

आर.एन.सच्ठेय, प्रत्यर्थी संख्या 1 की और से।

प्रेम मल्होत्रा, प्रत्यर्थी संख्या 2 की और से।

न्यायालय का आदेश इनके द्वारा दिया गया-

कृष्णा अय्यर, न्यायाधिपति.

इस मामले में अपील की अनुमति को अस्वीकार करने के हमारे कारणों को कुछ हद तक समझाने में हमें क्या बाधा है; अभिप्राय यह है कि कार्रवाई में न्याय के लिए प्रत्येक कार्यकारी चुनौती संबंधित कानून में कानूनी ताजगी भरकर जनता के विश्वास को मजबूत करने के लिए न्यायालय का आह्वान है जो कि आशंका की गई बुराई पर काबू पाने के लिए पर्याप्त है।

कहा जाता है कि याचिकाकर्ता के घर में चोरी हुई है और उसका आरोप है कि उसने कई कीमती सामान खो दिए हैं। सूचना मिलने पर पुलिस ने तलाशी ली और संपत्ति बरामद की। अंततः, विचारण न्यायालय ने हुसन लाल, एक जौहरी और मदन लाल, एक कथित सहयोगी (इस याचिका में प्रतिवादी संख्या 2 और 3) के खिलाफ धरा 411 आई.पी.सी. के तहत और एक अशोक कुमार के खिलाफ धारा 380 आई.पी.सी. के तहत आरोप तय किए। आपराधिक मामले की विचाराधीनता रहने के दौरान, सहायक लोक अभियोजक ने धारा 321 सी.आर.पी.सी. के तहत इस आधार पर अभियोजन वापस लेने के लिए आवेदन किया कि एक वरिष्ठ अधिकारी द्वारा ताजा जांच पर कथित तलाशी और जब्ती संबंधित पुलिस अधिकारी द्वारा एक साजिश के रूप में पाई गई थी ताकि आरोपी हुसन लाल पर एक निश्चित सिविल मुकदमे को वापस लेने के लिए दबाव डाला जा सके। न्यायालय में एक पूर्ण आवेदन की आवश्यकता पर सहायक लोक अभियोजक ने प्रत्याहरण के लिए एक नई और अधिक विस्तृत याचिका दायर की, जिसे याचिकाकर्ता के इस विरोध के बावजूद कि वापस लेने के लिए हुसन लाल द्वारा राजनीतिक प्रभाव के कारण प्रेरित किया गया था, जिसके कारण उच्च पक्षों ने सहायक लोक अभियोजक को उस आरोपी से संबंधित मामले से पीछे हटने का निर्देश दिया, अंततः विचारण न्यायालय ने मंजूर कर लिया। यह आरोप लगाया गया था कि निर्देशों का पालन करने में सहायक लोक अभियोजक ने एक स्वतंत्र दिमाग का उपयोग नहीं

किया। न्यायालय ने फिर भी सहायक लोक अभियोजक के अनुरोध को स्वीकार कर लिया और बाकी दो अभियुक्तों के खिलाफ मामला जारी रखते हुए हुसन लाल को दोषमुक्ति का निर्देश दिया। याचिकाकर्ता द्वारा उच्च न्यायालय के समक्ष पुनरीक्षण में आदेश के विरुद्ध असफल प्रयास किया गया। उस बर्खास्तगी से निडर होकर, उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत इस न्यायालय का रुख किया है। दोनों पक्षों के चौंका देने वाले खुलासों को देखते हुए हमने अभिलेख में हलफनामों के पूरक के रूप में मौखिक प्रस्तुतियों को कुछ हद तक सुना है।

तर्कों के तीन केंद्र बिंदु हैं कि क्या (i) कोई मामला जो न्यायालय में जाता है, न्यायाधीश को इसके बारे में जाने बिना दूसरी पुलिस अन्वेषण के अधीन हो सकता है, (ii) कार्यपालिका के राजनीतिक विचार लंबित कार्यवाही को प्रत्याहरित करने के प्रस्ताव को दूषित करते हैं, और (iii) लोक अभियोजक को सूचित और उसके द्वारा किए गए मामले से हटने का जिला मजिस्ट्रेट का आदेश, धारा 494 का अनुपालन है।

जब इस देश में कोई अपराध होता है, तो अपराध का आकलन और सजा देना या, वैकल्पिक रूप से, आरोपी को बरी करना या बरी करना देश की अदालतों द्वारा प्रशासित आपराधिक न्याय प्रक्रिया का हिस्सा है। आपराधिक न्याय दिलाना कार्यपालिका का कार्य नहीं है और हमारी प्रणाली में, न्यायाधीश परिवर्तनीय नहीं हैं, जैसा कि चांडलर [(1)] में जस्टिस डोंगल्स ने जोर देकर कहा है।

> "न्यायाधीश विनिमेय नहीं हैं; वे संवैधानिक स्पेक्ट्रम को कवर करते हैं; और जब साक्ष्य, न्यायालय कक्ष के मिजाज पर फैसले की बात आती है तो एक विशेष न्यायाधीश के जोर से बहुत फर्क पड़ सकता है। प्रस्तावित रक्षा के लिए सहनशीलता, इत्यादि। अधिवक्ता इसे तब पहचानते हैं जब वे किसी न्यायाधीश के लिए 'खरीदारी' की बात करते हैं; सीनेटर इसे तब पहचानते हैं जब उनसे न्यायिक नियुक्तियों के

लिए अपनी 'सलाह और सहमति' देने के लिए कहा जाता है; आम लोग इसे तब पहचानते हैं जब वे अपने समुदाय में न्यायपालिका की गुणवत्ता और छवि का मूल्यांकन करते हैं।"

जब कोई मामला आपराधिक न्यायालय में लंबित होता है तो उसकी प्रक्रिया और प्रगति दण्ड प्रक्रिया संहिता या अन्य प्रासंगिक क़ानून द्वारा नियंत्रित होती है। किसी न्यायालय में किसी जांच या विचारण को रोकने और वापस बुलाने के लिए, अधिनियम में प्रदान किए गए तरीके और सीमा को छोड़कर, स्वयं कानून का उल्लंघन है। जो कुछ भी करने की आवश्यकता है वह कानून के अनुसार किया जाना चाहिए। हमारे संवैधानिक आदेश के तहत न्याय देने का कार्य उन लोगों को सौंपा जाता है जिन्हें न्यायिक शक्ति सौंपी जाती है। न्यायालय की प्रक्रिया के निर्बाध प्रवाह के कुछ अपवादों में से एक धारा 321 सी.आर.पी.सी. है, लेकिन यहाँ भी यह लोक अभियोजक है, न कि कोई कार्यकारी प्राधिकारी, जिसे संहिता द्वारा अभियोजन से हटने की शक्ति सौंपी गई है, और वह भी न्यायालय की सहमति से। हम जोर देने के लिए दोहराते हैं। संहिता में दिए गए तरीके और सीमा को छोड़कर, किसी न्यायालय में किसी जांच या विचारण में हस्तक्षेप करना, रोकना या उसे रद्द करना अराजकता है। आपराधिक न्याय के समान मार्ग को कार्यपालिका द्वारा विफल नहीं किया जा सकता है, भले ही अभियुक्त कितना भी उच्च क्यों न हो, सरकार को लगता है कि कोई मामला झूठा है, लेकिन उन शक्तियों के लिए अभियोजन जारी रखना जो अहंकार, स्नेह या अन्य महान या अपमानजनक विचार के कारण न्यायालय के न्याय में बाधा डालना चाहते हैं। हमारे संवैधानिक आदेश के तहत न्याय करना न्यायाधीशों का काम है। न्यायिक प्रक्रिया के इस निर्बाध प्रवाह के बहुत कम अपवादों में से एक धारा 494, सी.आर.पी.सी. है, यहां भी, लोक अभियोजक - कोई कार्यकारी प्राधिकारी नहीं - संहिता द्वारा उसे न्यायालय की सहमति से

अभियोजन से पीछे हटने की सीमित शक्ति सौंपी गई है, जिसके बाद मामला समाप्त हो जाता है। कानून ने जो जलाया है, कानून ही उसे बुझाएगा।

हालांकि कंकाल, इस तरह के प्रत्याहरण के लिए शर्तें प्रावधान में निहित हैं, सामान्य सिद्धांतों के अलावा जो पूर्व निर्णय द्वारा से विकसित किए गए हैं। एक बार अभियोजन शुरू हो जाने के बाद, सार्वजनिक न्याय के लिए ठोस विचारों के अलावा इसके अथक पाठ्यक्रम को रोका नहीं जा सकता है। सारी सार्वजनिक शक्ति एक सार्वजनिक न्यास है, और लोक अभियोजक उस सार्वजनिक न्यास के निर्वहन के अलावा कार्य नहीं कर सकता है, जो सार्वजनिक न्याय के लिए तैयार एक सार्वजनिक न्यास है। प्रत्याहरण की शर्त के रूप में धारा 321 के तहत न्यायालय की सहमति उस शक्ति के प्रयोग पर एक जाँच के रूप में लगाई जाती है। सहमति तभी दी जाएगी जब इस तरह के प्रत्याहरण से व्यापक अर्थों में सार्वजनिक न्याय को बढ़ावा मिलेगा, न कि प्रभावित होगा। यही नोले प्रोसेकी न्यायशास्त्र का सार है।

हम इस बात पर जोर देना चाहते हैं, क्योंकि इस निषिद्ध आधार में कभी-कभी अस्वीकार्य प्रभाव घुसपैठ करते हैं, कि न्यायालय का न्याय कहीं और मालिकों और अनुचरों के लिए सीमा से बाहर है। हम धारा 494 सी.आर.पी.सी. के पीछे सार्वजनिक नीति के आयाम को कम नहीं करते हैं, लेकिन लोक अभियोजक को हल्के में लेते हुए इस नीति के प्रलोभन, मिलावट से सावधान रहना है। शायद, कार्यपालिका, बहुवचन चिंताओं और विविध कारणों से, एक आपराधिक मामले को रद्द करने की उचित इच्छा रख सकती है। तथ्य यह है कि सार्वजनिक शांति के व्यापक विचार, सार्वजनिक न्याय के व्यापक विचार और किसी इलाके में लंबे समय तक चलने वाली सुरक्षा को बढ़ावा देने के गहन विचार, एक अव्यवस्थित स्थिति में व्यवस्था या एक तथ्यात्मक परिवेश में सद्भाव, या एक न्यायालय में एक झूठे और परेशान करने वाले अभियोजन को रोकना, कार्यपालिका को स्वतंत्र रूप से राजी करता है, एक व्यापक लाभ के लिए एक

लंबित मामले का त्याग करता है, हालांकि शक्ति का संयम से प्रयोग किया जाना चाहिए और संतुष्ट होने के लिए वैधानिक एजेंसी लोक अभियोजक है, न कि जिला मजिस्ट्रेट या मंत्री। न्यायालय की सहमति आवश्यक है। अभियोजन पक्ष के पीछे एक धोखाधड़ी या आपराधिक कार्यवाही के लिए झूठे आधार का बाद में पता लगाना, जैसा कि इस मामले में आरोप लगाया गया है, वापस लेने के लिए एक प्रासंगिक आधार हो सकता है। क्योंकि निर्णायक रूप से नकली साबित हुए मामले को जारी रखने के लिए न्यायालय का दुरुपयोग नहीं किया जाना चाहिए। कानून का यह कथन संपूर्ण नहीं है, लेकिन वर्तमान उद्देश्य के लिए पर्याप्त है और वास्तव में, पूर्व निर्णय पर अच्छी तरह से आधारित है।

कानून और व्यवस्था का संवर्धन लोक न्याय का एक पहलू है। सार्वजनिक नीति के आधार पर अभियोजन वापस लेने की आवश्यकता हो सकती है। झूठा और परेशान करने वाले अभियोजन पक्ष को आगे बढ़ने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। आधार एक बड़े कैनवास को ढकते है। लेकिन शक्ति का सावधानीपूर्वक प्रयोग किया जाना चाहिए, और संतुष्ट होने वाली वैधानिक एजेंसी प्रथमतः लोक अभियोजक है, न कि जिला मजिस्ट्रेट या अन्य कार्यकारी प्राधिकारी। अंत में, न्यायालय की सहमति अनिवार्य है। एम.एन.संकरानारयाना नायर अन्य पी.वी. बाला कृष्ण और अन्य [(1)] में इस न्यायालय द्वारा कानून की व्याख्या की गई थी।

> "धारा 494 का एक पठन यह दर्शाएगा कि यह लोक अभियोजक है जो मामले का प्रभारी है जिसे किसी भी व्यक्ति के अभियोजन से या तो आम तौर पर या एक या एक से अधिक अपराधों के संबंध में वापस लेने के लिए न्यायालय की अनुमति लेनी चाहिए जिसके लिए उस पर विचारण चलाया जाता है। यह अनुमति उसके द्वारा किसी भी स्तर पर या तो जांच के दौरान या समर्पण के

बाद या फैसला सुनाए जाने से पहले भी ली जा सकती है। हालाँकि, यह धारा उन कारणों का संकेत नहीं देती है जिन पर लोक अभियोजक को अनुमति के लिए न्यायालय जाने के लिए विचार करना चाहिए और न ही उन आधारों का जिनके आधार पर न्यायालय अनुमति देगा या अस्वीकार करेगा। यद्यपि धारा सामान्य शब्दों में है और अभियोजन पक्ष से प्रत्याहरण की अनुमति लेने के लिए लोक अभियोजक की शक्तियों को सीमित नहीं करती है, लेकिन आवश्यक विचार जो शक्ति प्रदान करने में निहित है, वह यह है कि यह न्याय प्रशासन के हित में होना चाहिए जो या तो यह हो सकता है कि अभियोजन एजेंसी द्वारा अभियोजन पक्ष के साक्ष्य को गलत साबित करने से पहले पर्याप्त जानकारी प्रस्तुत करने में समर्थ नहीं होगी या कोई अन्य समान परिस्थितियां जो भविष्यवाणी करना मुश्किल है क्योंकि वे पूरी तरह से प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर हैं। फिर भी न्यायालय का यह कर्तव्य है कि वह न्याय को आगे बढ़ाने के लिए यह भी देखे कि अनुमति न्याय के हित से बाहर के आधारों पर नहीं मांगी गई है या जो अपराध राज्य के खिलाफ अपराध हैं, उन्हें केवल इसलिए दंडित नहीं किया जाता है क्योंकि सरकार सामान्य नीति या औचित्य के मामले में कानून के तहत अभियोजक अपराधियों के प्रति अपने कर्तव्य से असंबद्ध है और लोक अभियोजक को अभियोजन से हटने का निर्देश देती है और लोक अभियोजक केवल अपने कहने पर ऐसा करता है।"

बंसी लाल बनाम चंदन लाल [(2)] और बलवंत सिंह और अन्य बनाम बिहार[(3)] में स्थिति की पुष्टि की गई थी। इस प्रकार कानून सुस्थापित है और इसका उपयोग

सावधानी बरतने के लिए आवश्यक है। इस मामले की विशेष स्थिति में, दो सिद्धांतों को यहाँ रखा जाना चाहिए। प्रत्याहरण का निर्णय लोक अभियोजक का होना चाहिए, न कि अन्य अधिकारियों का, यहां तक कि उन लोगों का भी जिनकी नाराजगी उनके पद पर बने रहने को प्रभावित कर सकती है। न्यायालय निगरानीकर्ता है, सेवक नहीं, और उसे यह देखने के लिए जांच करनी चाहिए कि क्या कानून की अनिवार्यताओं का उल्लंघन नहीं किया गया है, निस्संदेह, सार्वजनिक अभियोजक की शक्ति को पंगु या हड़पने के बिना। जो दो बातें महत्वपूर्ण हैं वो ये हैं (ए) क्या विचार सार्थक हैं, और (बी) क्या वास्तविक निर्णय केवल लोक अभियोजक द्वारा किया गया था या उसका पालन किया गया था।

वर्तमान तथ्यों की स्थापना में, जांच यह होनी चाहिए कि क्या सहायक लोक अभियोजक द्वारा जिन विचारों को वापस लेने की मांग की गई थी, वे स्पष्ट और प्रासंगिक थे, और क्या प्रत्याहरण का वास्तविक निर्णय सहायक लोक अभियोजक द्वारा किया गया था या कार्यकारी प्राधिकारी के साथ अंधा अनुपालन का परिणाम था। यदि न्यायालय के समक्ष सामग्री से यह प्रतीत होता है कि स्पस्ट या प्रासंगिक विचारों ने प्रस्ताव को प्रत्याहरण के लिए प्रेरित नहीं किया, लेकिन यह राजनीतिक प्रभाव का दबाव था, तो न्यायालय अपनी सहमति को रोक देगा।

अभियोजन से हटने की शक्ति वाला संहिता द्वारा धारण किया गया अधिकारी लोक अभियोजक है। लोक अभियोजक कार्यकारी नहीं है, न ही राजनीतिक शक्ति का एक झुंड है जिसे कानून द्वारा वापस लेने या वापस न लेने के विवेक के साथ निवेश किया गया है, यह उस पर निर्भर है कि वह स्वतंत्र दिमाग लगाए और अपने विवेक का प्रयोग करे। ऐसा करते हुए, वह न्यायिक प्रक्रिया के एक अंग के रूप में कार्य करता है, न कि कार्यपालिका के विस्तार के रूप में।

वर्तमान मामले में, ऐसा प्रतीत होता है कि जब न्यायालय ने कार्यवाही शुरू की, तो आरोपी हुसन लाल ने उच्च पुलिस अधिकारियों से शिकायत की कि संबंधित सहायक उप-निरीक्षक ने केवल एक करीबी रिश्तेदार के खिलाफ वाद में समझौता करने के उस पर दबाव बनाने के उद्देश्य से मामला शुरू किया था। एक वरिष्ठ अधिकारी द्वारा आरोपों की जांच की गई और जिला मजिस्ट्रेट ने सामने आने वाली सामग्री के आधार पर सहायक उप-निरीक्षक के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई का निर्देश दिया और सहायक लोक अभियोजक को हुसन लाल के खिलाफ मामले से हटने का निर्देश दिया। हमें राजनीतिक प्रभाव के आरोपों के समर्थन में कोई सबूत नहीं मिलता है। साथ ही, यह इंगित करना आवश्यक है कि जिला मजिस्ट्रेट ने सहायक लोक अभियोजक को प्रत्याहरण का निर्देश देने में अवैध रूप से काम किया। यह आरोप लगाया गया है कि कार्यकारी पक्ष की ओर से मामले की दूसरी जांच, जिसके कारण यह पता चला कि पिछली जांच प्रेरित थी, पहले मुखबिर से पूछताछ करने की चूक के कारण खराब हो गई थी। यह सहायक लोक अभियोजक के लिए अभियोजन से हटने या न हटने का निर्णय लेते समय विचार करने का मामला था।

इस मामले में उत्पन्न होने वाले प्रमुख प्रश्न पर, रिकॉर्ड से पता चलता है कि लोक अभियोजक ने दूसरी जांच से सामने आने वाले खुलासों पर अपना दिमाग लगाया, और उन्होंने पाया कि "यहां तक कि वसूली के गवाह सर्वश्री माटो राम और फूल सिंह ने भी इस बात का समर्थन नहीं किया कि उन्होंने वसूली देखी थी या मदन लाल आरोपी द्वारा उनकी उपस्थिति में कोई खुलासा बयान दिया गया था।" उन्होंने पाया कि फूल सिंह उस समय बिस्तर पर थे और उनकी मृत्यु हो चुकी थी। उन्होंने यह भी पाया कि मातो राम ने कहा था कि उनकी उपस्थिति में कुछ भी नहीं हुआ था लेकिन जांच अधिकारी ने उनके हस्ताक्षर ले लिये थे। यह पूरी तरह से स्पष्ट है कि सहायक लोक

अभियोजक ने अपने सामने मौजूद सामग्री पर स्वतंत्र निर्णय लिया और जिला मजिस्ट्रेट के निर्देशों का अंधाधुंध अनुपालन नहीं किया।

हम प्रत्याहरण की कार्यवाही में जिला मजिस्ट्रेट की बेहद परेशान करने वाली उपस्थिति की ओर ध्यान आकर्षित किए बिना इस याचिका का निपटारा नहीं कर सकते।। छल-कपट का न्यायशास्त्र हमारी प्रणाली के लिए अलग है और कानून अपेक्षा करता है कि आदेशों, निर्देशों, धमकियों और प्रलोभनों की परवाह किए बिना शक्ति का प्रत्येक भंडार संविधान और कानूनों द्वारा अपना कर्तव्य निभाए। संहिता आपराधिक प्रक्रिया के लिए मास्टर है। कोई भी प्राधिकारी जो लोक अभियोजक जैसे किसी पदाधिकारी को उसके विवेकाधिकार के अनन्य प्रांत में मजबूर करता है या आदेश देता है या दबाव डालता है, कानून के शासन का उल्लंघन करता है और कोई भी लोक अभियोजक जो इस तरह के आदेश के सामने झुकता है, उसके कार्यालय के अधिकार के साथ विश्वासघात करता है। हो सकता है, सरकार या जिला मजिस्ट्रेट इस बात पर विचार करेगा कि कोई अभियोजन या अभियोजन का वर्ग नीति या कानून और न्याय के लिए प्रासंगिक जनहित के कारणों के आधार पर उनके व्यापक अर्थ में वापस लेने के योग्य है और लोक अभियोजक से इस बात पर विचार करने का अनुरोध करेगा कि क्या मामला या मामले वापस नहीं लिए जा सकते हैं। इसके बाद, अभियोजक प्रस्तुत सामग्री, सिफारिश के पीछे की नीति और सरकार की जिम्मेदार स्थिति को उचित महत्व देगा, जिसे अंतिम विश्लेषण में, सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखना और सार्वजनिक न्याय को बढ़ावा देना है। लेकिन पीछे हटने का निर्णय उनका ही होना चाहिए।

जिला मजिस्ट्रेट जो एक कार्यकारी अधिकारी है, लोक अभियोजक नहीं है और उसे आदेश भी नहीं दे सकता है। हो सकता है कि अधिकारी ने लोक अभियोजक की स्वायत्त स्थिति या वापस लेने का आदेश देकर लोक अभियोजक के विवेक में अपनी

घुसपैठ की अनुचितता के बारे में खुद को अवगत नहीं कराया था। इसी तरह की गलतियाँ विभिन्न स्तरों पर आम होती जा रही हैं और इसलिए हमें कानून की स्थिति को पूरी तरह से स्पष्ट करना पड़ा है। हम इस बात पर जोर देते हैं कि कानून का शासन कार्यकारी अधिकारियों को मामलों को वापस लेने के मामले में न्यायसंगत प्रक्रिया से सावधान करता है। चूंकि हम संतुष्ट हैं कि लोक अभियोजक ने जिला मजिस्ट्रेट के निर्देश को नहीं माना, बल्कि न्यायालय के समक्ष रखी गई सामग्री के बारे में खुद को सूचित करने का एक स्वतंत्र अध्ययन किया और फिर अभियोजन पक्ष से प्रत्याहरण की अनुमति मांगी, इसलिए हम निचले न्यायालयों द्वारा पारित आदेश को उलटने से इनकार करते हैं।

विचारण न्यायालय संतुष्ट थी कि सहायक लोक अभियोजक ने किसी भी अवैध उद्देश्य के लिए प्रत्याहरण की शक्ति का प्रयोग नहीं किया था और उच्च न्यायालय ने उस निष्कर्ष का समर्थन किया। हम उच्च न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप करने के लिए तैयार नहीं हैं।

याचिकाकर्ता की एक स्पष्ट शिकायत को दूर किया जाना चाहिए। वह अपना चुराया हुआ सामान वापस पाने में रुचि रखता है। अभियुक्त माल में किसी संपत्ति का दावा नहीं करता है। शिकायतकर्ता द्वारा उन्हें अपनी संपत्ति के रूप में पहचानने की स्थिति में, विचारण न्यायालय उन्हें वापस करने के लिए उचित आदेश पारित करने पर विचार करेगी। निश्चित रूप से, आपराधिक न्याय के कई आयाम हैं जो दोषसिद्धि और सजा, दोषमुक्ति और निर्दोषता से परे हैं। पीड़ित को भुलाया नहीं जाना चाहिए, लेकिन जहां तक संभव हो उसे बहाल किया जाना चाहिए।

याचिका खारिज की जाती है।

एन.के.ए.

याचिका खारिज की गई।

(1) चंद्रेलर बनाम अमेरिका के दशवें सर्किट की न्यायिक परिषद्, 308 यू.एस. 74, 1970

(1) ए.आई.आर. 1972 एस.सी. 496

(2) ए.आई.आर. 1976 एस.सी. 370

(3) ए.आई.आर. 1977 एस.सी. 2265

यह अनुवाद आर्टिफ़िश्यल इंटेलिजेंस टूल "सुवास" की सहायता से अनुवादक अधिवक्ता विनायक कुमार जोशी द्वारा किया गया है ।

अस्वीकरण- इस निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और अधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।

*****